प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 28 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 08 – 15 जुलाई 2019 मूल्य पांच रूपए

एनजीटी आदेश के परिदृश्य में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश पर उठते सवाल

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और उनकी टीम प्रदेश में औद्योगिक निवेश जुटाने के लिये पिछले कुछ अरसे से अपने देश से लेकर विदेशों तक यात्राएं करके प्रयास कर रहे हैं। उनके इन प्रयासों से करीब 80,000 करोड़ के एमओयू साईन होने की जानकारी विभिन्न सरकारी विज्ञप्तियों के माध्यम से जनता में आयी है। जो एमओयू साईन हुए हैं उनसे अभी ज्यादा खुश होने की भी बात नही है क्योंकि इनमें निवेशकों की ओर से इतना ही भरोसा है कि वह यहां निवेश करने को ईच्छुक हैं और सरकार की ओर से यह आश्वासन है कि वह निवेशकों को इसमें पूरा सहयोग करेगी। इस भरोसे और आश्वासन को अमली शक्ल लेने में कितना समय लगेगा यह कहना संभव नही है। निवेश को लेकर शंकायें केन्द्र का बजट आने के बाद ज्यादा उभरी हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ही निवेशकों का करीब छः लाख करोड़ डूब गया है। स्वभाविक है कि जब देश में ही निवेशक नही आयेगा तो प्रदेश में कैसे आयेगा।

इस परिप्रेक्ष में यह आकलन करना आवश्यक हो जाता है कि प्रदेश में चल रहे उद्योगों की वर्तमान में स्थिति क्या है क्योंकि इससे पहले रहे दोनों मुख्यमन्त्रीयों प्रेम कुमार धूमल और वीरभद्र सिंह के काल में भी ऐसे प्रयास हुए हैं और इन्ही प्रयासो के बाद दोनों सरकारों पर "**हिमाचल ऑन सेल**" के आरोप भी लगे है। पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से हर मुख्यमन्त्री के बजट भाषण में प्रदेश में सैटलाईट टाऊन बनाने की घोषणाएं दर्ज हैं लेकिन व्यवहार में अब तक कुछ नही हो पाया है। इसलिये यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या जिस तरह के औद्योगिक विकास की परिकल्पना लेकर हम चले हुए हैं क्या वह प्रदेश के लिये व्यवहारिक भी है या नही। क्योंकि प्रदेश को विद्युत राज्य बनाते – बनाते आज यह परियोजनाएं एक संकट का कारक बनती नजर आ रही है विभिन्न अध्ययन रिपोर्टो से यह सामने आ चुका है। अब तक के औद्योगिक विकास से प्रदेश को क्या हासिल हुआ है उसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व में तो कोई बड़ा योगदान नही रहा है लेकिन इससे जीडीपी का आंकड़ा बढ़ने से कर्ज लेने की सीमा बढ़ती चली गयी और आज प्रदेश 52000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और रोजगार कार्यालयों में दर्ज बेरोजगारों की संस्था भी दस लाख के करीब हो चुकी है। इसी परिदृश्य में यदि पिछले एक दशक के आंकड़ो पर नजर डाले तो सरकार के ही आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2009 – 10 में कुल 36315 उद्योग ईकाईयां प्रदेश में पंजीकृत थी जिनमें मध्यम और बड़ी ईकाईयों की संख्या 428 थी। इनमें 8936.57 करोड़ का निवेश था तथा 2.35 लाख लोगों को रोजगार हासिल था। 2018 – 19 में आज ईकाईयों की संख्या 49058 हो गयी है जिनमें 140 बड़ी और 522 मध्यम हैं लेकिन इनमें निवेश कितना है और इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला है इसको लेकर आर्थिक सर्वेक्षण में कोई जिक्र नही है। 31 – 12 – 2014 तक 40,429 ईकाईयां पंजीकृत थी और इनमें 18307.95 करोड़ का निवेश था तथा 2,84599 लोगों को रोजगार हासिल था।

प्रदेश में स्थापित उद्योगों के माध्यम से अब तक तीन लाख से कम लोगों को रोजगार हासिल हो पाया है इसमें भी रोजगार पाने वाले सभी हिमाचली नही है। लेकिन सरकार की ओर से 40 औद्योगिक बस्तियों और 15 एस्टेट्स के विकास पर करोड़ो रूपया खर्च किया गया है। पंडोगा में 88.05 और कन्दरोड़ी में 95.77 करोड़ आधारभूत ढ़ाचा विकसित करने में खर्च किया गया है। उद्योगों के लिये 781701 बीघा का भूमि बैंक तैयार करने के अतिरिक्त दमोटा में 515 बीघा वन भूमि ली गई है इसके अतिरिक्त विभिन्न समयों पर उद्योगों को जो सुविधा पैकेजों के माध्यम से दी गयी है यदि उसका पूरा विवरण खंगाला जाये तो उस रकम का जो ब्याज बनता है वह उद्योगों से मिलने वाले राजस्व से शायद दो गुणा से भी अधिक होगा।

आज प्रदेश में एनजीटी के आदेश के बाद निमार्ण कार्यो पर लगभग रोक जैसी स्थिति बनी हुई है। प्रदेश सरकार को अभी तक सर्वोच्च न्यायालय से कोई राहत नही मिल पायी है और राहत की संभावना भी नही के बराबर है क्योंकि पूरा प्रदेश अधिकांश में सिस्मक जोन पांच में आता है। अधिकांश परियोजनाएं इसी जोन में स्थित हैं इसलिये यहां और स्थापनाओं से पर्यावरण के लिये और संकट बढ़ जायेगा। पर्यावरण के असन्तुलन के खतरे को सामने रखते हुये यह संभव नही लगता है कि अढ़ाई मंजिला से अधिक के निमार्ण की अनुमति मिल पायेगी। एनजीटी का आदेश इसी सचिवालय के बड़े बाबूओं की कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है और आज वही बाबू बाहर से निवेशक लाने के प्रयासों में लगे हैं। टीसीपी एक्ट पूरे प्रदेश में लागू है और उसी के कारण एनजीटी का आदेश भी सभी जगह लागू है। सरकार टीसीपी एक्ट में संशोधन करने की बात कर रही है लेकिन क्या इससे पहले रैगुलर प्लान नही लाना होगा। 1979 से अन्तरिम प्लान के सहारे ही काम चलाया जा रहा था और उसमें भी एक दर्जन से अधिक संशोधन किये गये है। सरकार की इन्ही विसंगतियों के कारण यह मामला एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा है। ऐसे में जब तक सरकार इन विसंगतियों को दूर नही कर लेती है तब तक कोई भी निवेशक यहां निवेश का जोखिम नही ले पायेगा। क्योंकि अढ़ाई मंजिल का आदेश उसके सामने आ जायेगा। अवैध निमार्णो को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक कड़ा संज्ञान लेकर दोषीयों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के निर्देश दे चुके हैं। गौरतलब यह है कि ऐसे सभी मामलों में संवद्ध प्रशासन ने नियमों कानूनो की जानबुझ कर अनदेखी की है और इस अनदेखी का नुकसान पूरे प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। आज ठीक यही स्थिति इस प्रस्तावित औद्योगिक विकास में फिर घटती दिख रही है। क्योंकि इसमें सुधार अधिनियम की धारा 118 से लेकर टीसीपी एक्ट और एनजीटी के फैसले जैसे कई गंभीर मुद्दों पर खुली चर्चा की आवश्यकता है।

क्या शिमला के भराड़ी में भी कसौली कांड घटने की तैयारी हो रही है

लोक निर्माण विभाग के नोटिस से उभरी आशंका

शिमला/शैल। राजधानी शिमला के उपनगर भराड़ी के दुधली गांव क्षेत्र से देवीधार जाने वाली सड़क के किनारे करीब एक दशक पहले से बने आठ भवनों के मालिकों को लोक निर्माण विभाग के डिविजन न. 1 शिमला के कनिष्ठ अभियन्ता ने 15 दिन के भीतर अपने भवन तोड़ने के नोटिस जारी किये हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता श्रवण डोगरा सहित उर्मिला ठाकुर, राजकुमार, सीमा सूद, रविन्द्र ठाकुर, राजेश चौहान, हीरा सिंह वर्मा और मोहन सिंह के खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने रोड़ साईड़ Control Width के तीन मीटर दायरे के भीतर मकान बनाकर एक्ट की उल्लंघना की है। स्मरणीय है कि प्रदेश उच्च न्यायलय ने एक समय यह निर्देश जारी किये थे कि इलेजियम/देवीधार सड़क की चौड़ाई वाहन चलाने योग्य होनी है। उच्च न्यायालय के इन निर्देशों पर कितना और क्या अमल हुआ है इसकी जानकारी एक आरटीआई के माध्यम से एक डॉ. बन्टा ने 11.5.18 को मांगी थी। इस आर टीआई के परिणाम स्वरूप अब एक साल बाद यह नोटिस भेजने की कारवाई की गयी है।

इन नोटिसों से जो सवाल खड़े हुए हैं वह महत्वपूर्ण हैं और पूरे तन्त्र की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हैं। स्मरणीय है कि यह मकान और यह सड़क उच्च न्यायालय के निर्देशों से बहुत पहले बने हैं और तभी रोडसाईड एक्ट का उल्लंघना हो चुकी थी। एक्ट में तो पहले दिन से ही यह मौजूद है कि कन्ट्रोल width के 3 मीटर के दायरे के भीतर बिना अनुमति के निर्माण नहीं हो सकता। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब यह निर्माण शुरू हुए थे तब लोक निर्माण विभाग का संवाच्छित प्रशासन कहां था। उसने उस समय इन निर्माणों का संज्ञान लेकर तब ऐसा ही नोटिस भेजने की कारवाई क्यों नहीं की। फिर भराडी क्षेत्र टीसीपी और नगर निगम शिमला दोनों के दायरे में आता है। इसलिये स्वभाविक है कि इन भवनों के नक्शे भी संबद्ध अथारिटी से पास करवाये ही गये होंगे। यदि यह भवन नक्शा पास करवा कर बनाये गये हैं तो उस समय नक्शा पास करने से पहले इस एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित क्यों नहीं की।

यदि भवन निर्माण के समय लोकनिर्माण विभाग और टी सी पी या नगर निगम शिमला ने इस ओर ध्यान नही दिया है तो क्या आज भवन मालिकों के मकान गिराने से पहले संबद्ध विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ कारवाई नही की जानी चाहिये। क्योंकि यह नोटिस देने से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इसमें एक्ट की उल्लंघना तो हुई ही है। हो सकता है कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही उल्लंघनाएं हुई हों और आज भी हो रही हों। आज जब भराड़ी क्षेत्र में इन मकानों को गिराने की कारवाई होगी तो क्या वहां भी एक और कसौली कांड घटने की सम्भावना नही बन जाती है।

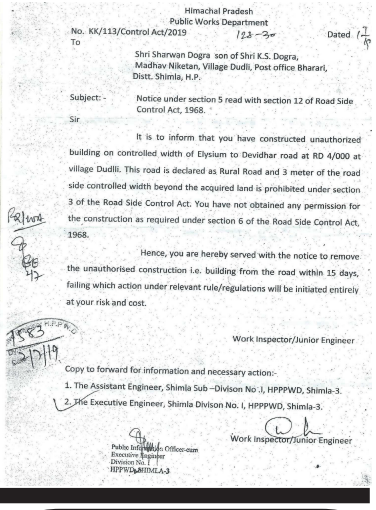

Himachal Pradesh
Public Works Department

No. KK/113/Control Act/2019 Dated 1-7-19

To

Shri Sharwan Dogra son of Shri K.S. Dogra,
Madhav Niketan, Village Dudli, Post office Bharari,
Distt. Shimla, H.P.

Subject:- Notice under section 5 read with section 12 of Road Side Control Act, 1968.

Sir

It is to inform that you have constructed unauthorized building on controlled width of Elysium to Devidhar road at RD 4/000 at village Dudlli. This road is declared as Rural Road and 3 meter of the road side controlled width beyond the acquired land is prohibited under section 3 of the Road Side Control Act. You have not obtained any permission for the construction as required under section 6 of the Road Side Control Act, 1968.

Hence, you are hereby served with the notice to remove the unauthorised construction i.e. building from the road within 15 days, failing which action under relevant rule/regulations will be initiated entirely at your risk and cost.

Work Inspector/Junior Engineer

Copy to forward for information and necessary action:-

1. The Assistant Engineer, Shimla Sub –Divison No -I, HPPPWD, Shimla-3.
2. The Executive Engineer, Shimla Divison No. I, HPPPWD, Shimla-3.

Work Inspector/Junior Engineer

Public Information Officer-cum
Executive Engineer
Division No. I
HPPWD, SHIMLA-3

हिमाचल प्रदेश में योजना एवं वास्तुकला स्कूल खोलने की केन्द्र सरकार से मांग

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात करके उनसे हिमाचल में केंद्रीय वित्त पोषित योजना एवं वास्तुकला संस्थान स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा राष्ट्रीय महत्त्व के इस संस्थान के खुलने से हिमालय वास्तुकला के संरक्षण के साथ-साथ पर्वतीय वास्तुकला के अध्ययन-अध्यापन हेतु मदद मिलेगी और प्रदेश के युवाओं के लिए यह संस्थान वरदान साबित होगा।

बिक्रम सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के एक छोटे और पर्वतीय राज्य होने के कारण यहां सीमित संसाधन हैं और प्रदेश के हजारों युवक जोकि योजना एवं वास्तु कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें इस प्रदेश में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस संस्थान की स्थापना के लिए अनिवार्य भूमि तथा अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा यह संस्थान पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी अध्ययन एवं अध्यापन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय देश में नई दिल्ली, भोपाल तथा विजयवाड़ा में राष्ट्रीय महत्त्व के तीन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर कार्यरत हैं और हिमाचल प्रदेश में इस संस्थान के खुलने से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एक मील पत्थर साबित होगा।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह को भरोसा दिलाया कि भविष्य में जब भी ऐसे संस्थान खोले जाएंगे, हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी जाएगी।

जन प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों को डिजिटलीकरण से जोड़ा जाएगा:डॉ.राजीव बिन्दल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल ने विधानसभा द्वारा विकसित सॉफटवेयर 'ई-कन्स्टिचुअन्सी मेनेजमेंट' तथा

'ई-कमेटी सिस्टम' के प्रति उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए मुख्य सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ई-कन्स्टिचुअन्सी मेनेजमेंट को प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है तथा जिला व उप-मण्डल स्तर पर कार्यालय प्रमुखों को यूजर आईडी तथा पासवर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि विधायकों की सहायता से लोगों की समस्याओं का समय पर निवारण हो सके।

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में वर्ष 2018 के दौरान ई-विधान सॉफटवेयर प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं आयोजित की गई। इस सॉफटवेयर में विधायकों को ई-विधान मोबाइल तथा वैब डैशबोर्ड के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे विधायक अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न पत्रचार तथा कार्रवाई की निगरानी कर सकेगें।

उन्होंने कहा कि ई-कमेटी सिस्टम को विधानसभा कमेटियों तथा सरकारी विभागों के मध्य कागजरहित पत्रचार के लिए विकसित किया गया है। इस सिस्टम के तहत हाउस कमेटियां सम्बन्धित विभाग को मूल पत्र अथवा ऑनलाइन रिमाईण्डर भेज सकती हैं। इस सॉफटवेयर के माध्यम से लम्बित पड़े मामलों, पिछले रिकॉर्ड, रिपोर्ट तथा सुझाव ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों से इन सॉफटवेयरों के माध्यम से प्रदेश में एक मजबूत व प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार के उपयोगी सॉफटवेयरों को विकसित कर विधानसभा प्रशासन ने एक नई पहल की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी व्यवस्था के माध्यम से जनता के प्रतिनिधियों तथा सरकारी अधिकारियों के बीच एक सुदृढ़ तालमेल कायम होगा, जिससे निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

बैठक के दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी धार्मेश शर्मा ने 'ई-कन्स्टिचुअन्सी मेनेजमेंट' तथा 'ई-कमेटी सिस्टम' और विधानसभा द्वारा की जा रही अन्य गतिविधियों के बारे में एक प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निशा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आयुर्वेद संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव शहरी विकास प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जगदीश चन्द्र, प्रधान सचिव शिक्षा कमलेश कुमार पन्त तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा सहित विधानसभा के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कॉरिस्पान्डेंस तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा:अनिल खाची

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची की अध्यक्षता में गैर बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एनबीएफसी) विषय पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक भारतीय रिज़र्व बैंक की पंजाब, हिमाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ की क्षेत्रीय निदेशक रचना दीक्षित द्वारा आयोजित की गई।

अनिल खाची ने इस अवसर पर बैंकिंग कॉरिस्पान्डेंस (बी.सी) तंत्र को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को बेहतर करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बी.सी द्वारा दी जा रही सेवाओं का उपयोग माईक्रो एटीएम के माध्यम से बैंक लेन-देन के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने राज्य को आर्थिक अपराधों से मुक्त बनाने के लिए सभी कोशिशें करने पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को आर्थिक अपराधों के संबंध में जागरूक करने के लिए और अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि इस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य के नौ जिलों में 15 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और इसके अतिरिक्त बैंक के द्वारा जिला शिमला, कुल्लू और मण्डी में पांच प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। एसईबीआई ने भी इस दौरान राज्य में 148 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

क्षेत्रीय निदेशक रचना दीक्षित ने इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक, चण्डीगढ़ द्वारा एनबीएफसी के विरूद्ध सुपरवाईजर एक्शन और नई पहल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

प्रधान सचिव (कानून) यशवंत सिंह छोगल, ए.डी.जी (सीआईडी) अशोक तिवारी, आईजी (क्राईम एण्ड सीआईडी) ज्ञानेश्वर सिंह, भारतीय रिजर्व बैंक के महा प्रबंधक के.सी आनंद और डॉ. डी. पी पांडा और भारतीय रिजर्व बैंक, एसईबीआई और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

मुख्यमंत्री ने बचाव कार्य की निगरानी के लिए किया कुमारहट्टी का दौरा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन के कुमारहट्टी में हुई दुर्घटना की स्थिति पता करने के लिए दुर्घटनास्थल का दौरा किया, जहां रविवार को एक होटल भवन के धसने से 30 जवानों और 12 आम नागरिकों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी।

इस हादसे में 13 सेना के जवानों की मृत्यु और 17 जवान घायल हुए जबकि एक आम नागरिक की मृत्यु और 11 आम नागरिक घायल हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, राज्य पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे संयुक्त अभियान की निगरानी करते हुए प्रशासन को एनडीआरएफ को हर सम्भव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए, जिससे उन्हें अभियान को चलाने में कोई कठिनाई न हो।

हादसे में घायलों का कुशलक्षेम जानने के लिए मुख्यमंत्री जिला सोलन के सिविल अस्पताल धर्मपुर और महार्षि मार्कण्डेश्वर चिकित्सा महाविद्यालय, कुमारहट्टी भी गए।

मुख्यमंत्री ने इस दुःखद हादसे में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए, कहा कि राहत कार्य में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ की तीन अतिरिक्त कम्पनियां घटना स्थल पर भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुन्नी से आधुनिक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ के दल को लाने के लिए हैलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और भवन के मालिक के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।

रोगियों व उनके तीमारदारों को हिमाचल भवन नई दिल्ली में डोरमेट्री सुविधा आरम्भ

शिमला/शैल। नई दिल्ली में उपचार करवाने आए हिमाचल प्रदेश के रोगियों व उनके तीमारदारों को ठहरने के लिए इधर-उधर न भटकना पड़े, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की पहल पर हिमाचल भवन नई दिल्ली में महिला व पुरुष रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए दो अलग-अलग डोरमेट्री सुविधा आरम्भ कर दी गई हैं। इन दोनों डोरमेट्री में 6-6 बिस्तर उपलब्ध हैं और यह पूर्णतया वातानुकूलित हैं।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इससे पहले हिमाचल भवन नई दिल्ली में प्रदेश के उन विद्यार्थियों के लिए भी दो डोरमेट्री बनाने के निर्देश दिए थे, जो पढ़ाई या परीक्षाओं के सिलसिले में दिल्ली आते हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना के तहत हिमाचल भवन नई दिल्ली में लड़के व लड़कियों के ठहराव के लिए लिए दो अलग-अलग डोरमेट्री पहले ही आरम्भ की जा चुकी है और अब नई दिल्ली में उपचार करवाने आने वाले हिमाचल के रोगियों व तीमारदारों के लिए भी दो अलग-अलग डोरमेट्री आरम्भ कर दी गई है। पहले रोगियों व तीमारदारों को दिल्ली में ठहराव के लिए बहुत कठिनाईयां पेश आती थी, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत आवासीय आयुक्त व पर्यटन निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा इन दोनों डोरमेट्री को बहुत कम समय में तैयार करके पूर्णतया सुविधा संपन्न बनाया गया है। रोगियों व उनके तीमारदारों ने मुख्यमंत्री की पहल पर उपलब्ध करवाई गई इस सुविधा के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।

हिमाचल भवन नई दिल्ली के वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि इन दोनों डोरमेट्री में पूर्व आरक्षण करवाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के शिमला स्थित दूरभाष नंबर 0177-2880426 पर आवेदन किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त हिमाचल भवन नई दिल्ली के रिसेप्शन काउंटर के दूरभाष नंबर 011-23716124 पर संपर्क किया जा सकता है, जहां उपलब्धता के आधार पर इस सुविधा को हासिल किया जा सकेगा।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
INVITATION FOR BIDS (IFB)
01905-272269 FAX:-272862 EMAIL: EE-DHAR-HP@NIC.IN
No: PW-DPD-CB-TENDER/2019: DATED:

The Executive Engineer, Dharampur Division, HPPWD Dharampur , Distt: Mandi (H.P) on behalf of Governor of H.P invites the item rate bids, in electronic tendering systems from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the work as detailed in the table.

Sr..No.	Name of Work	Estimated cost (In Rs.)	Starting Date for downloading Bid	Earnest Money (In Rs.)	Deadline for submission of bid
	C/o Joh Nansai Tayog road Km 0/0 to 2/0 (SH: Formation Cutting 5/7 mtr wide road in Km 1/150 to 1/315)	5,03,965/-	18.07.2019	11,000/-	01.08.2019

The bidders are advised to note other details of tender from the department website **www.hptenders.gov.in.**

Adv. No.-0950/19-20 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

23 हजार करोड़ के निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 23 हजार करोड़ रुपए के निवेश को लेकर एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं तथा हिमाचल विकास की राह में आगे बढ़े के लिए तैयार है।

जय राम ठाकुर ने मंडी सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को लेकर समग्र दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश आए। इस उद्देश्य के तहत पिछले दिनों देश-विदेश में आयोजित रोड शो और राजनायिकों एवं बड़े उद्यमियों से मुलाकात करके निवेश आकर्षित करने को ईमानदार प्रयास किए गए हैं। इनसे देश व दुनिया में हिमाचल की ब्रांर्डिंग हुई है।

उन्होंने कहा कि उद्यमियों को हिमाचल में निवेश के लिए मौजूद उपयुक्त माहौल, मजबूत कानून व्यवस्था, शांत, शुद्ध एवं प्रदूषणमुक्त वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता एवं सस्ती दरों जैसी सुविधाओं से अवगत करवाया गया है। ये सभी विशेषताएं हिमाचल को निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाती हैं। इससे हिमाचल की ओर निवेशकों का रूझान बढ़ा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 व 8 नवम्बर, 2019 को धर्मशाला में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी। यहां निवेशकों और उद्यमियों का एकजुट होना अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन लाएगा। पर्यटकों के लिए बिलासपुर और मंडी में नए पर्यटन स्थल विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मंडी में शिवधाम बनाने और ब्यास नदी पर झील विकसित करने की योजना पर भी काम हो रहा है। सरकार प्रयास कर रही है कि मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए रास्ते में घूमने व ठहरने के लिए उपयुक्त स्थलों को विकसित की जाएं।

पुलिस मामलों में शामिल छात्रों को न दिया जाए होस्टल

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक प्रतिनिधिमण्डल राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिला और उन्हें अपनी मांगों से सम्बन्धित ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें छात्रों ने मांग की कि मार्च माह में विश्वविद्यालय में हुई हिंसा को लेकर गठित फेक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिर्पोट को सार्वजनिक किया जाए।

इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी मांग की कि हिंसा में संलिप्त छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित किया जाए तथा पुलिस मामलों में संलिप्त छात्रों को किसी भी तरह की हॉस्टल सुविधा न दी जाए। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय में हिंसा के मामले में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी शांतिपूर्ण माहौल में बेहतर ढंग से शिक्षा प्राप्त कर सकें।

राज्य में भूकम्प पर मेगा मॉक अभ्यास आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सहयोग से भूकम्प मैगा-मॉक का अभ्यास किया, जिसमें प्रदेश के सभी 12 जिलों ने भाग लिया। इस अभ्यास के लिए यह परिदृश्य बनाया गया कि प्रदेश में रात के समय रिक्टर पैमाने पर 8 मैगनिटयूड का भूकम्प आया है, जिसका केन्द्र मण्डी जिला का सुन्दरनगर होगा।

प्रधान सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन ओंकार शर्मा ने कहा कि भूकम्प को इसलिए चुना गया, क्योंकि राज्य भूकम्प के जोन चार और जोन पांच के अन्तर्गत आता है तथा इस कारण राज्य के लिए यह प्रमुख खतरा है। उन्होंने कहा कि इस परिदृश्य का विकास एनडीएमए, आईआईटी मुम्बई और मद्रास के तकनीकी सहयोग से किया गया। उन्होंने कहा कि भूकम्प के कारण अन्य कई दूसरी आपदाएं जैसे भू-स्खलन, भवनों एवं पुलों का गिरना, आग, बांध विफलता और चट्टानों का गिरना आदि हो सकती हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दृष्टिगत 3 जुलाई को मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल की अध्यक्षता में अनुकूलन सहयोग सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई को टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य, जिला, सेना, वायु सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, सीआईएसएफ और एसएसबी के लगभग 460 अधिकारियों ने भाग लिया। मॉक अभ्यास प्रात: 8:30 बजे ट्रिगर किया गया और राज्य एवं जिला आपातकाल अभियान केन्द्रों (ईओसीज) को तुरन्त सक्रिय किया गया और इंसिडेंट रिसपॉन्स टीमें (आईआरटी) अपने-अपने ईओसीज पर पहुंची।

ओंकार शर्मा ने कहा कि जिलावार परिस्थितियां एसडीएमए द्वारा दी गई और जिलों को 112 घटना स्थल दिए गए थे और इस अभ्यास में 2650 अधिकारियों के साथ 32 गैर सरकारी संगठनों के 833 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान आए काल्पनिक भूकम्प में मोबाइल एवं लैंड-लाइन सुविधा बाधित होने की स्थिति को मानते हुए आज 836 वायरलैस सेट और 62 आई-सेट फोन प्रयोग में लाए गए। उन्होंने कहा कि अभ्यास के दौरान विभिन्न गतिविधियां जैसे बचाव एवं राहत, प्रभावितों को परिवहन सुविधा, राहत शिविरों का प्रबन्ध, यातायात नियंतरण, कानून व्यवस्था, मॉक सन्देशों के रूप में एसईओसी को स्थिति की जानकारी, राज्य मुख्यालय से आवश्यक सहायता के सम्बन्ध में प्रोजेक्शन, हवाई अड्डों और चिन्हित हैलीबेसिज़ का एक्टिवेशन, क्षति एवं हानि मूल्यांकन प्रक्रिया की कार्रवाई की गई।

उन्होंने कहा कि मैगा मॉक अभ्यास का उद्देश्य राज्य, जिला और आपदा प्रबंधन विभाग की योजनाओं की प्रतिक्रिया योजना की दक्षता व समीक्षा करना है ताकि इससे आपातकाल प्रतिक्रिया योजना और जिले की संचालन प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जा सके और हिस्सेदारों की जिम्मेदारे व कर्तव्य को उजागर किया जा सके ताकि हिस्सेदारों के मध्य समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके और आम जनता में जागरूकता लाई जा सके और कमजोरियों को चिन्हित किया जा सके।

वरिष्ठ परमर्शदाता, राष्ट्रीय प्राधिकरण (एनडीआरएफ), मेजर जनरल (सेवानिवृत) वी.के. नाइक ने इस मॉक अभ्यास के दौरान विभिन्न एजेंसियों, एसइओसी और डीइओसी की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया तथा पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रयोग में लाए गए संचार नेटवर्क की कम्पैटिबिल्टि की भी जांच की। उन्होंने कहा कि मॉक अभ्यास का संचालन एनडीएमए द्वारा विकसित इंसिडेंट रिसपान्स सिस्टम (आईआरएस) के अनुसार संचालित की गई, जिसमें और अधिक सुधार किए जाएंगे।

निदेशक व विशेष सचिव राजस्व व आपदा प्रबन्धन डी.सी राणा ने कहा कि हमें पिछली घटनाओं से व आज के अभ्यास को व्यावहारिक रूप से लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एसडीएमए द्वारा राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए उपकरण व विशेष औजार खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को 8.16 करोड़ रुपये, पुलिस को पुलिस आपदा प्रतिक्रिया संचार योजना के लिए 4.28 करोड़ रुपये, गृह रक्षा विभाग को 14 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाए गए है। उन्होंने कहा कि इस पर कुल 26.78 करोड़ रुपये व्यय किए गए है।

उन्होंने कहा कि राज्य में संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस और एसडीएमए ने 62 आई-सैट फोन खरीदे है तथा लाहौल-स्पीति को 8 अधिक आई-सैट फोन शीघ्र ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के लिए 75 वी-सैट फोन स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि इस अभ्यास के दौरान हैलीकॉप्टर उडान भरने के लिए तैयार था लेकिन खराब मौसम के चलते नहीं उड़ सका।

पुलिस अभ्यास के महानिरीक्षक हिमांशु मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने धर्मशाला, मण्डी और शिमला में तीन मोबाईल संचार वैन उपलब्ध करवाई है जिनमें संचालक के साथ सैटेलाईट फोन, वायरलैस संचार और वीएचएफ भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वायरलैस सैट, आई-सैट भी इस्तेमाल किए गए।

बाद में डीब्रीफींग भी की गई जिसमें ओंकार शर्मा, वी.के नायक, सेना और अर्धसेना बल के अफसरों ने उपायुक्तों से विडियो कांफ्रेसिंग द्वारा बातचीत की। ओंकार शर्मा ने कहा कि आज कि मैगा मॉक अभ्यास गत वर्ष फरवरी में आयोजित मॉक ड्रिल की तुलना में काफी संतोषजनक रहा। उन्होंने कहा कि इससे हमें अपनी ताकतें और कमज़ोरियां आंकने में सहायता मिली है। उन्होंने उपायुक्तों से जिला आपदा प्रबंधन योजना को वर्तमान मौजूदा स्थिति के अनुसार स्तरोन्नत करने को कहा। उन्होंने कहा कि उप-मण्डल व जिला स्तर पर मॉक अभ्यास आयोजित करने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि और अधिक सैटेलाईट फोन जोड़े जाएंगे और ईओसीएस को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा और स्वयं सेवियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सेना द्वारा जिला शिमला में जतोग इंफेन्ट्री बटालियन से 11 कॉलम और 7 निरीक्षक उपलब्ध करवाए गए। इस अभ्यास के दौरान बीआरो व वायुसेना के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। अस्पतालों की तत्परता का निरीक्षण करने के लिए सेना के स्वास्थ्य अधिकारी भी तैनात किए गए थे। आईटीबीपी द्वारा शिमला में दो कॉलम व कुल्लू और रिकांगपिओ में एक-एक टुकड़ी व काज़ा में एक प्लटून तथा ऑबजर्वर उपलब्ध कराए गए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाईन जल्द करेगी जनता की समस्याओं का समाधान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (हिम सेवा)' की शिमला मण्डलीय क्षेत्र के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान अहमदाबाद (गुजरात) से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करेगी तथा लोगों को सरकारी कार्यालयों में बार-बार अपने कार्य के लिए जाने से राहत प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में आरम्भ किया गया जनमंच कार्यक्रम सफलतापूर्वक लोगों की समस्याओं का निदान कर रहा है। इसी उद्देश्य से बजट की घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री हेल्पलाईन आरम्भ की जाएगी, जिससे आधुनिक तकनीक का उपयोग कर लोगों के समय तथा पैसे की बचत होगी। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मुख्यमंत्री हेल्पलाईन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें तथा प्रदेश सरकार पर जनता के विश्वास को बनाए रखने में सहयोग दें।

प्रधान सचिव सूचना प्रौद्योगिकी जगदीश चन्द्र ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन राज्य सरकार द्वारा लोगों के हित में किए गए प्रयासों को दर्शाती है। हेल्पलाईन के तहत समस्त विभागों से सम्बन्धित शिकायत दर्ज की जाएगी तथा उन पर शीघ्र कार्रवाई कर निवारण किया जाएगा। यह हेल्पलाईन कॉल सेंटर के माध्यम से विभिन्न शिकायतों तथा मांगों को पंजीकृत करेगी तथा इस उद्देश्य के लिए विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारियों की जानकारी भी हेल्पलाईन पर उपलब्ध होगी। हेल्पलाईन के माध्यम से लोगों की प्रतिक्रिया व सुझाव भी प्राप्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन मोबाइल ऐप भी आरम्भ की जाएगी।

निदेशक सूचना प्रौद्योगिक रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाईन के तहत चार स्तरों पर शिकायत के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें खण्ड स्तर, जिला स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर तथा राज्य स्तर शामिल हैं। हेल्पलाईन की निगरानी मुख्य सचिव तथा मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। यह हेल्पलाईन प्रात: 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यशील रहेगी। निर्धारित समय में समस्या का निदान न होने पर इसे अगले स्तर पर कार्यवाही के लिए भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन मण्डी व कांगड़ा स्थित धर्मशाला में भी किया जाएगा।

अवैध खनन पर कड़ी कारवाई के निर्देश:बिक्रम सिंह ठाकुर

शिमला/शैल। उद्योग, श्रम एवं रोजगार तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने जिला कांगड़ा की इंदौरा तहसील के डमटाल, माजरा, टिपरी तथा ज्वाली क्षेत्र में अतिरिक्त एसपी (मुख्यालय) कांगड़ा, खनन अधिकारी नूरपुर, डीएसपी नूरपुर, एसएचओ इंदौरा तथा जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों सहित औचक निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य को पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने तथा प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में कानून व नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वर्तमान अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है ताकि वे प्रदेश में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर सकें। उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा दोषियों को राज्य के कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैर कानूनी खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी।

उद्योग मंत्री ने निरीक्षण के दौरान 18 क्रशर तथा 12 माइनिंग लीज की जांच की। आठ माइनिंग लीज क्षेत्रों में खनन नियमों का उल्लंघन पाया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को दोषी पाए गए प्रत्येक लीज धारक पर नियमों के अनुसार 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य के हैडवर्कज स्ट्रक्चर की सुरक्षा तथा लोक ढांचों के समीप अवैध खनन से सम्बन्धित सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य की शिकायतों के कारण ज्वाली अप्स्ट्रीम में एक माइनिंग लीज तथा मानव स्टोन क्रशर को प्रदान किए गए सिद्धांत हैडवर्कज को निरस्त करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर अवैध खनन गतिविधियों के कुल चार मामले पाए गए, जिसमें एक ट्रेक्टर, एक जेसीबी तथा दो टिप्परों को कब्जे में लिया गया और जुर्माना लगाया गया।

बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि नदी के किनारों पर अवैध खनन गतिविधियां को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे तथा अवैध खनन गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं।.....चाणक्य

सम्पादकीय

क्या दलबदल से भाजपा कांग्रेस मुक्त करायेगी देश को

लोकसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित हार के बाद विपक्ष में टूटन शुरू हो गयी है। टीडीपी के चारों राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गये हैं। टीडीपी के बाद आई एन एल डी का सांसद भी भाजपा में चला गया है। इन सांसदों के बाद गोवा के दस कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गये। उनमें से तीन मन्त्री भी बन गये हैं। कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों ने त्यागपत्र देकर गठनबन्धन सरकार के लिये संकट पैदा कर दिया है। कर्नाटक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच चुका है। प्रधान न्यायधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के बाद अब यह मामला पांच जजों की पीठ को सौंपा गया है। देश की शीर्ष अदालत में इस प्रकरण के आने के बाद यह स्पष्ट हो जायेगा कि हमारा दल बदल विरोधी कानून कितना सक्ष्म है। इसमें कांग्रेस या भाजपा जिसकी भी जीत हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जनमत की हार निश्चित है। कर्नाटक प्रकरण में भाजपा अपना हाथ होने से इन्कार कर रही लेकिन भाजपा नेतृत्व वहां मेन केन प्रकारेण सरकार बनाने के लिये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गोवा और कर्नाटक के प्रकरण कब बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोहरा दिये जायें यह अब सामान्य लग रहा है। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने बंगाल को लेकर तो अपने इरादे लोकसभा चुनावों में ही जाहिर कर दिये थे और वहां वैसा ही घटता भी जा रहा है।

यह जो कुछ हो रहा है इससे सबसे पहला सवाल यह उभरता है कि इस तरह के राजनीतिक जन प्रतिनिधियों के सहारे देश का लोकतन्त्र कैसे कितनी देर जिंदा रहेगा। दूसरा सवाल शीर्ष न्यायपालिका को लेकर उठता है कि वहां सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को कितनी देर तक लटकाये रखा जायेगा। इस समय दो महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित चल रहे हैं एक में बीस लाख ईवीएम मशीनों के गायब होने का मामला है। सवाल स्पष्ट है कि या तो मशीने गायब होने का आरोप सच है या निराधार है। अदालत में यह मामला आरटीआई के तहत मिली सूचना पर आधारित है। यदि मशीने गायब होने का आरोप सही साबित हो जाता है तो फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों पर बात आयेगी और उसके परिणाम दूरगामी होंगे। लेकिन इससे दलों की हार जीत से अलग लोकतन्त्र की जो जीत होगी वह महत्वपूर्ण है। अदालत में एक याचिका लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर केन्द्र और कुछ राज्यों द्वारा जो जनता के कुछ वर्गो को वित्तिय लाभ देने के लिये जो योजनाएं घोषित की गयी तथा उनके तहत यह वित्तिय लाभ दिये भी गये इसे मतदाताओं को प्रलोभित करना माना जाये। एक अरसे से यह चलन बन गया है कि सरकारें चुनावों से पूर्व ऐसी योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर सार्वजनिक रूप से घूसखोरी को अंजाम देती हैं और लोकतन्त्र फिर हार जाता है। आज यह मुद्दे याचिकाओं के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के पास लंबित पड़े हैं और उन्हे कोई प्राथमिकता नही दी जा रही है। क्या ऐसे न्यायपालिका पर भी लम्बे समय तक विश्वास बना रह पायेगा।

आज जिस तरह से यह दलबदल घट रहा है उससे जहां जन प्रतिनिधियों की विश्वनीयता सवालों के घेरे में खड़ी हो गयी है। वहीं पर राजनीतिक दलों की विश्वनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं गोवा में कांग्रेस के विधायकों को मन्त्री बनाने के लिये दूसरे घटक के मन्त्रीयों को हटाना पड़ा उन्होने स्वेच्छा से अपने पद नही त्यागे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बड़े पैमाने पर सौदेबाजी को अंजाम दिया गया। यहां यह सवाल उठता है कि क्या भाजपा को यह सब करने की आवश्यकता थी? जो पार्टी अभी इतना बड़ा जन विश्वास लेकर सता में आयी है क्या उसके ऐसे आचरण से पापुलर जनमत हासिल करने के दावों पर स्वत: ही प्रश्नचिन्ह नही लग जाता है। क्या भाजपा कर्नाटक प्रकरण का पटाक्षेप होने से पहले यह घोषणा करने का दम रखती है कि वह दलबदल से सरकार नही बनायेगी और राज्य में चुनाव करवायेगी। भाजपा में यह दम नही है क्योंकि इसी कर्नाटक लोकसभा चुनावों के मतदान के बाद मतगणना से पहले हुए निकाय चुनावों में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। क्या इस तरह के राजनीतिक आरचण से भाजपा का अपना ही पक्ष कमजोर नही हो रहा है।

मोदी सरकार–2 का पहला बजट हवा–हवाई और आकाशी

गौतम चौधरी

किसी राष्ट्र के इतिहास में यह दुर्लभ क्षण होता है, जब वह दो अंकों की मध्यम अवधि की विकास गति को आगे बढ़ा सकता है। हमारा देश इस मामले में विगत कई वर्षो से पिछड़ता रहा है। ऐसे में मोदी सरकार ने इस देश की कमान सम्भाली थी जब देश का विकास दर आठ और नौ के बीच था लेकिन मोदी सरकार के दौरान देश का विकास दर लगातार घट रहा है। सरकार को इस परिस्थिति का अंदाजा लगाकर अपनी आर्थिक रणनीति तय करनी चाहिए लेकिन विगत दिनों प्रस्तुत बजट पर इस आर्थिक दबाव का कोई असर नहीं दिखा। मोदी सरकार–2 ने ऐसे समय कार्यभार संभाला है, जब विकास दर की गिरावट और तेज हुई है। मसलन वर्ष 2018–19 के दौरान विभिन्न तिमाहियों में विकास दर क्रमश: 8.7, 6.6 से घटकर 5.8 फीसदी तक पहुंच गयी है। ऐसी खतरनाक परिस्थिति में नए मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) ने मोदी सरकार के लिए लक्ष्य तय किए हैं। भारत का लक्ष्य 2024–25 तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है, जिससे वह दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इस लक्ष्य में बड़े पैमाने पर अंतरविरोध दिख रहा है। ऐसा लगता है कि यह लक्ष्य हवा में तय किया गया है। जैसे–इस अर्थव्यवस्था को पाने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति की दर चार फीसदी निर्धारित की है। उसे देखते हुए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वास्तविक विकास दर आठ फीसदी होना जरूरी है। परंतु फिलहाल किसी कीमत पर यह संभव नहीं है। क्योंकि दुनियाभर में मंदी का दौर अभी और भयावह होना है। दूसरी ओर अमेरिकी आर्थिक राष्ट्रवाद के कारण अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को स्वदेशी मॉडल प्रदान कर रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सेवा सेक्टर पर टिकी हुई है। यदि अमेरिका ने इस सेक्टर में ऑउटसोर्स बंद कर दिया तो यह संकट और गहरा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमारा बाजार निर्यात पर कम और आयात पर ज्यादा निर्भर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी प्रचंड राष्ट्रवाद के सामने चीन भी बहुत जल्द ही हथियार डाल देगा। तब भारत को और ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आने वाले समय में 8 प्रतिशत का विकास दर प्राप्त करना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। अब सवाल यहा है कि मोदी सरकार 2 का पहला बजट (बही–खाता) लक्ष्य की ओर कितना आगे बढता दिख रहा है?

अक्तूबर, 2018 में अंतरराष्ट्रीय ख्याति के तेरह अर्थशास्त्रियों ने 14 शोध पत्र तैयार किए, जो 2019 में ''व्हाट इकोनॉमी नीड्स नाऊ (अर्थव्यवस्था को अभी किस चीज की जरूरत है)'' शीर्षक से प्रकाशित हुए। ये सारे अर्थशास्त्री भारतीय या भारतीय मूल के हैं। सभी अर्थशास्त्रियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा पर गंभीर चिंता जताई है। मोदी सरकार 2 के प्रथम बजट में उन अर्थशास्त्रियों की चिंता को भी सिरे से खारिज कर दिया गया है।

इधर राजकोषीय घाटे पर अंकुश

लगाने में मोदी सरकार का रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, जो अभी भी जारी है। मोदी सरकार अपने पहले शासन के पांच वर्षो के दौरान राजकोषीय घाटे को 4.5 फीसदी से 3.4 फीसदी तक कम करने में ही सफल रही है। अब सरकार ने 2019–2020 के बजट में इसे 3.3 फीसदी तक नीचे लाने का वादा किया गया है, जिसकी संभावना दूर–दूर तक नहीं दिख रही है। वित्तमंत्री के भाषण में कृषि क्षेत्र के तनाव को कम करने के किसी भी तरह के उपाय का जिक्र नहीं किया गया। यह साबित करता है कि मोदी सरकार दो की नजर में कृषि क्षेत्र की समस्या अब खत्म हो गयी है। यह सरकार की नियत पर सवाल खड़ा कर रहा है। जिस पार्टी की सरकार के नुमाइंदे अपने पहले कार्यकाल में लगातार यह कहते रहे कि हम किसानों की आय को दुगुनी करेंगे, उसी पार्टी की सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसान, खेती–किसानी गायब है। यह साबित करता है कि या तो किसानों की समस्या खत्म हो गयी है या फिर सरकार किसान को खत्म करने की गहरी साजिश कर रही है। मोदी सरकार दो के पहले बजट में बिजली के बारे में इसमें मौजूदा योजना उदय को ही दोहराया गया है, जिसका लक्ष्य वितरण कंपनियों के वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना है। यानी बिजली के उत्पादन पर कोई मुकम्मल योजना नहीं बनाई जाएगी। यह भी खतरनाक है। इसका साफ मतलब है कि अब देश में बिजली उत्पादन की पूरी व्यवस्था निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा। सरकार बिजली के विपणन और वितरण पर ध्यान देगी। इसका क्या असर होगा इसका अंदाजा लगाना अभी संभव नहीं है लेकिन पावर सेक्टर के निजी क्षेत्र में चले जाने के बाद देश पूरी तरह से निजी क्षेत्र के हाथ में चला जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के बारे में भी इस बजट में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। मसलन सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 70,000 करोड़ रुपये (यह पूरी तरह से नाकाफी है) उपलब्ध कराने और बैंकों को वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी की जमा संपत्तियों को खरीदने के लिए छह माह में एक बार आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने का वादा किया गया है। यह पूरी तरह अपर्याप्त है।

बता दें कि वर्तमान दौर में बैंक, कृषि और बिजली के क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है लेकिन सरकार इस दिशा में पहल करने के बदले गोलमोल बात कर रही है। आपको बता दें कि यह तीनों क्षेत्र किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम होता है। कुल मिलाकर देखें तो मोदी सरकार पार्ट टू का यह पहला बजट उपर से देखने में चाहे जितना संतुलित लगे लेकिन लक्ष्य से भटका हुआ–सा प्रतीत होता है। देश की अर्थव्यवस्था को मौलिक सुधारों की जरूरत है, जैसा कि 1991–96 के दौरान किया गया था। यही नहीं बिजली, बैंक और कृषि के क्षेत्र में बड़े निवेश की जरूरत है। खासकर कृषि के क्षेत्र में अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रतिकूल असर पड़ेगा। सरकार के पास ऐसे सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए जनादेश प्राप्त है। बिना किसी स्पष्टीकरण के सरकार ने वृद्धिशील सुधारों का रास्ता चुना है। ये सुधार देशहित में नहीं दिख रहा है। सरकार को आधारभूत संरचना के साथ–साथ आधारभूत अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। पहले जमाने में किसी देश की अर्थव्यवस्था कपड़ा, लोहा एवं इस्पात और पेट्रोलियम उद्योग पर आधारित होता था लेकिन अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उस देश की कृषि और सेवा क्षेत्र अहम भूमिका होती है। बैंकिंग और बिजली क्षेत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मोदी सरकार के इस बजट में देश के आधारभूत संरचना पर तो ध्यान दी गयी है लेकिन इस संरचना के निर्माण के लिए पूंजी का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि मोदी सरकार पार्ट टू का पहला बजट हवा–हवाई और आकाशी है।

भारत नहीं हारा.... क्रिकेट हार गया

''पूण्य प्रसून वाजपेयी''

क्रिकेट विश्व कप से भारत बाहर हो गया। दोष किसका है, किसका नहीं। सेमीफाईनल में न्यूजीलैंड ने अपनी फिल्डिंग और गेंदबाजी के दम पर भारत को हरा दिया, गलती किसकी है किसी की नहीं। तो क्या वाकई हम एक ऐसे दौर में आ चुके है जहां अपने अपने क्षेत्र के नाकाबिल कप्तान हार के बावजूद दोषी नहीं होते है। कप्तान विराट कोहली ने शुरुआती पैंतालिस मिनट के खेल को दोषी करार देकर दो दिन तक चले न्यूजीलैंड के मुकाबले में हार को महज इत्तेफाक कहकर खामोशी बरत ली और भारत के तमाम लोगों ने मान लिया इससे बेहत भारतीय टीम हो नहीं सकती तो फिर 'वेलडन ब्याज' के आसरे जश्न में कोई कमी रहनी नहीं चाहिये इसे भी दिखा दिया। सिवाय देश के मुख्य न्यायधीश के अलावा पीएम से लकर सीएम तक और कैबिनेट मंत्रियो से लेकर धराशायी विपक्ष के नेताओं ने भी सोशल मीडिया पर टीम इंडिया की हौसला अफजाही करते हुये हार से कुछ इस तरह मुंह मोडा जैसे क्रिकेट के जश्न में कोई खलल पडनी नहीं चाहिये। आखिर बीसीसीआई दुनिया के सबसे ताकतवर खेल संगठन के तौर पर है। जिसका टर्नओवर बाकि नौ देशो के क्रिकेट संगठनो के कुल टर्नओवर से ज्यादा है तो फिर गम काहे का। और आईपीएल में तो सभी को कमाने-खाने भारत ही आना है। फिर भारत फाइनल में नहीं होगा तो लाड्स के फाइनल को देखने कौन पहुंचेगा, और विज्ञापन से कमाई भी थम जायेगी। टीवी राइटस से भी आईसीसी की कमाई में पचास फिसदी तक की कमी आ जायेगी तो गम काहे का। और अब भारतीय क्रिक्रेट प्रेमी रविवार को लाडस का फाइनल देखने की जगह बिबलंडन का फाइनल देखेगें जिसमें नडाल या फेडरर में से कोई तो पहुंचेगा ही। क्योंकि शुक्रवार यानी 12 जुलाई को सेमीफाईनल में यही दोनों टकरा रहे हैं। यानी टीवी पर विज्ञापनो का हुजुम क्रिकेट से निकल कर टेनिस में समा जायेगा। क्योंकि भारतीय कंज्यूमर या कहे भारतीय बाजार क्रिकेट विश्व कप नहीं बल्कि विम्बलडन देख रहा होगा। तो पूंजी, बाजार का जश्न-जोश जब चरम पर हो और उस पर राष्ट्रवाद चस्पा हो तब क्रिकेट का मतलब सिर्फ खेल नहीं बल्कि देश को जीना होता है और देश कभी हारता नहीं। तो हार कर भी भारतीय टीम हारी नहीं है ये सोच जगाकर जरा सोचना शुरु किजिये आखिर हुआ क्या जो भारतीय टीम हार गई।

कही कप्तान की कप्तानी का अंदाज कुछ ऐसा तो नहीं हो चला था जहां वह जो करें वही ठीक। क्योंकि पहले चालीस मिनट में रोहित और विजय के साथ विराट भी पैवेलियन वापिस लौट आये थे और यहीं से शुरु होता है कि आखिर कप्तान का मतलब होता क्या है और जीतने वाली न्यूजीलैंड टीम के कप्तान की पीठ कोई क्यो ठोंक रहा है जबकि उसके दो धुरंधर गेंदबाज बोल्ट और हेनरी ने कमाल किया। लेकिन विश्वकप के फाइनल मोड पर टीम के संयम और सटीक फिल्डिंग का जो अनुशासन न्यूलीलैंड के कप्तान विलियम्सन ने दिया वह अद्भूत था। लेकिन दूसरी तरफ तीन विकेट गिरने के बाद कार्तिक की जगह धोनी क्यों नहीं मैदान में उतारे गये कोई नहीं जानता। फिर रिषभ पंत पर भरोसा विश्वकप के बीच में क्यों जागा और भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में तीन विकेटकीपर टीम इलेवन में खेल रहे हैं ये भी अपनी तरह का नायाब दौर रहा। जडेजा इंग्लैण्ड के खिलाफ क्यों मैदान में नहीं थे। और शमी झटके में कैसे बाहर हो गये। कोई नहीं जानता। यानी चालिस मिनट में ढहढहायी टीम इंडिया के कप्तान के पास प्लान बी क्या था। ये सबकुछ जानते हुये भी कोई नहीं जानता क्योंकि हर किसी को याद होगा विश्वकप से पहले जब तमाम टीम आपस में वार्म-अप मैच खेल रही थी तब भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ऐसी ही ढहढहायी थी। कुल जमा 179 रन भारत ने बनाये थे और तब भी जडेजा ही एकमात्र खिलाडी थे जिन्होंने पचास रन ठोके थे। यानी न्यूजीलण्ड के तेवर को प्रेक्टिस मैच में भारत देख चुकी थी और याद कीजियेगा तो उस प्रेकटिस मैच में भी मौसम बिगडा हुआ था। तब कोहली ने 'ओवरकास्ट' यानी मौसम को दोष दिया था और उसके बाद कोहली ने टीम इलेवन को लेकर जो सोचा वह किया। फिर कोच रवि शास्त्री की नियुक्ति तक पर जब कप्तान कोहली की चलने लगी हो तब मान लिजिये भारतीय क्रिकेट अपने अंहकार के चरम पर है और हुआ यही है कप्तान की मनमर्जी या भारतीय क्रिकेट फैन्स का दीवानापन या बीसीसीआई की रईसी या फिर क्रिकेट को धर्म मानते हुये सचिन को भगवान मानने की पुरानी रीत के आगे अब क्रिकेट का जुनुन छद्म राष्ट्रवाद में समा चुका है। जिसे कोई खोना नहीं चाहता है तो अठारह राज्यों के सीएम, देश के सोलह कैबिनेट मंत्री और विपक्ष में गांधी परिवार से लेकर क्षत्रपो की एक कतार भारतीय टीम का ढांढस इसलिये बंधाती है क्योंकि उसे पता चल चुका है अब कप्तान के होने का मतलब क्या है। और खेल भावना सिर्फ कप्तान के साथ खड़े होने में ही क्यों है। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा भी जब सत्तानुकुल हो चुकी होगी तो फिर कर्नाटक या गोवा में पाले बदलने से लेकर पाला बदलने से रोकने वालो को ही मुबंई के होटल के बाहर पुलिस गिरफ्तार करने से चुकेगी नहीं। यानी विकल्प हर किसी के पास कम हो चले हैं। राजनीति कहती है या तो सत्ता के साथ आ जाओ तमाम सुविधा मिलेगी नहीं आओगे तो जांच एंजेसी आपके दरवाजे पर खडी है। खेल कहता है, कप्तान के साथ खडे हो जाओ तो सभी खेलते रहेंगे नहीं तो अंबाती रायडू की तरह सन्यास लेना पडेगा। फैन्स कहते हैं, इंडिया, इंडिया। बाकि आप जो सोचते हैं उसका कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि देश मान चुका है भारत हारा नहीं है क्रिकेट हारा है। क्योंकि बिना भारत विश्वकप क्रिकेट का क्या महत्व है। कोअ्र देखने वाला ना होगा, कोई सट्टा लगाने वाला ना होगा, कोई विज्ञापन देने वाला ना होगा तो क्रिकेट ने बाजार गंवाया और हम क्रिकेट में हार कर भी क्रिकेट के बाजार में सबसे ज्यादा मुनाफा पाने वालो में हैं।

हिमाचल में साहसिक खेलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के प्रयास

हिमाचल प्रदेश में साहसिक खेलों को व्यापक बढ़ावा देकर इस दिशा में नए आयाम स्थापित किए हैं और इस प्रदेश ने भारत के 'एडवेंचर हब' रूप में विश्वभर में अपनी पहचान बनाई है। साहसिक खेलों व साहसिक पर्यटन में नाम अर्जित करने के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबद्ध खेल संस्थान, मनाली का विशेष योगदान रहा है।

साहसिक खेलों और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण व संबद्ध खेल संस्थान की स्थापना मनाली में सन् 1961 में की थी। इस संस्थान के माध्यम से सरकार देश के स्कीयर, ट्रेकर और पर्वतारोहियों को विशेष प्रशिक्षण कोर्स के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। यह संस्थान सरकार द्वारा हिमांच्छादित पर्वतों तथा कठिन ट्रेकिंग मार्गों पर चलाए जाने वाले बचाव एवं राहत कार्यों में भी सहायता प्रदान करता है क्योंकि संस्थान के पास बचाव कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति/अमला मौजूद है।

प्रदेश की जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अनेक साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। यह प्रदेश पर्यटकों को मनमोहक दृश्य और अद्भुत अनुभवों के साथ-साथ, अविस्मरणीय साहसिक अनुभव भी उपलब्ध करवाता है। खेल प्रेमी पैराग्लाईडिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग, पर्वतारोहण और जोरबिंग जैसी गतिविधियों का आनन्द ले सकते हैं।

राज्य सरकार ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तत्तापानी और लारजी बांध जल क्रीड़ायें आरम्भ करने के लिए चिन्हित किया है। पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान मनाली को इन स्थलों पर शीघ्र आवश्यक अधोसंरचना और अन्य सुविधाओं को सृजित करने का कार्य सौंपा गया है। इन स्थानों पर पर्यटकों को हाइड्रो फोलिंग, वाटर स्कूटर तथा जेट वेटोर जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

प्रदेश में साहसिक खेलों को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में भी कारगर कदम उठाए जा रहे हैं तथा समय-समय पर प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही के अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली में 25 लोगों को 14 दिवसीय राफ्टिंग कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया तथा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राफ्टिंग लाईसेंस जारी किए गए।

पैराग्लाईडिंग पॉयलट की योग्यता की जांच करने के लिए भी संस्थान द्वारा एक प्रोसिटी मशीन स्थापित की गई है जो ग्लाईडर की क्षमता की जांच करती है। इन गतिविधियों के अलावा संस्थान द्वारा उपभोक्ताओं को 150 रुपये देने पर पांच लाख रुपये तक का बीमा व पॉयलटों को 550 रुपये सालाना प्रीमियम अदा करने पर 10 लाख रुपये की बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है।

साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष मार्च माह में अतंरराष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा का सफल आयोजन किया, जिसमें विश्व के विभिन्न देशों की 40 टीमों ने ट्रेकिंग, मैराथन, माउंटेन बाईकिंग तथा राफ्टिंग जैसे साहसिक खेलों में भाग लिया। इन साहसिक खेलों के दौरान आयोजित दौड़ 450 किलोमीटर की दूरी तय कर जंजैहली से होते हुए मनाली से शिमला पहुंची। यह आयोजन राज्य को साहसिक खेलों के गंतव्य के रूप में लोकप्रिय बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है।

यही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान मनाली की राफ्टिंग टीम ने इस वर्ष जून माह में तुर्की में आयोजित वर्ल्ड राफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिससे प्रदेश को विश्वस्तर पर पहचान मिली है।

खेल एवं युवा सेवा मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने जानकारी दी है कि हिमाचल प्रदेश अगले वर्ष आयोजित होने वाले पहले एशियन राफ्टिंग चैम्पियनशिप कप की मेज़बानी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक सुनियोजित ढंग से साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई खेल नीति लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय फैसिलिटेटर की भूमिका निभाकर प्रधानमंत्री की सोच को देगा मूर्त रूप

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उस समय ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना जब नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने के उद्देश्य से लगभग 50 देशों के राजनयिकों को राज्य में निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वे अपने-अपने देश के उद्यमियों, निवेशकों तथा व्यापार संघों को हिमाचल में अपनी पसंद के क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर निवेश करने के लिए प्रेरित व सहयोग करें।

इस अवसर पर विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरण ने कहा कि धर्मशाला में 7 व 8 नवंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में पूरे विश्व के निवेशकों व व्यापार संघों को आमंत्रित किया जाना राज्य सरकार की एक अनूठी व अनुकरणीय पहल है और विदेश मंत्रालय इसमें फैसिलिटेटर की भूमिका निभाएगा। उन्होंने हिमाचल की आर्थिकी को समृद्ध करने और इसे देश-विदेश के निवेशकों का पसंदीदा निवेश स्थल बनाने बारे मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के विजन व राज्य सरकार की नीतियां की सराहना की।

उन्होंने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और केंद्र सरकार ने मेक-इन इंडिया व स्टार्टअप-इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू करके देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करने की कारगर पहल की है।

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरण ने कहा कि वर्षों से नीति-निमार्ता इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं कि भारत में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) को कैसे तीव्र करते हुए भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिया' अभियान का श्रीगणेश करके यह काम कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य निवेश को सुविधाजनक बनाना, नवाचार को

बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना, बौद्धिक संपदा को सुरक्षा देना तथा सर्वोत्तम श्रेणी का मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करना है।

उन्होंने कहा धौलाधार कि नयनाभिराम पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे धर्मशाला नगर में वैश्विक इन्वेस्टर मीट आयोजित होने से राज्य में पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे, विश्व भर से आए लोग हिमाचल प्रदेश की गौरवपूर्ण संस्कृति व परंपराओं से भी साक्षात्कार कर पाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास रंग लाएंगे और हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेश गंतव्य के तौर पर दुनिया के मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित होने वाली प्रथम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को मूर्त रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा प्राकृतिक सौंदर्य व प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हिमाचल में बेहतर अधोसंरचना, निवेश मैत्री माहौल, शांत वातावरण और सरकार की उदार नीतियां संभावित निवेशकों तथा प्रदेश के लोगों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा प्रदेश को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने के प्रयासों में प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरणा ले रही है जिन्होंने भारत की आर्थिकी को वर्ष 2024 तक 5 खरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बेहतर अधोसंरचना सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में शत-प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा आधार पर अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध है। प्रदेश में राज्य के सभी भागों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय तथा राज्य उच्च मार्गो का व्यापक नेटवर्क है। उन्होंने कहा दूरदर्शी नीतियों व योजनाओं को प्रभावी तरीके से अमलीजामा पहुंचाने के कारण हिमाचल विकास के ऐसे स्थान पर पहुंच चुका है, जहां से हम और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं तथा वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए देश के सभी राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि विदेश राज्य मंत्री का इस अवसर पर उपस्थित होना हमारे लिए गौरव की बात है। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न देशों के राजनयिकों से आग्रह किया कि वे हिमाचल प्रदेश को वैश्विक निवेश स्थल बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों में अपनी सहभागिता निभाते हुए अपने देशों के उद्यमियों तक राज्य सरकार के संदेश को पहुंचाएं ताकि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को ऐतिहासिक सम्मेलन बनाया जा सके।

इस अवसर पर प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग उत्पाद, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, कपड़ा इत्यादि क्षेत्रों में ग्लोबल ब्रांड कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में विनिर्माण आर्थिक की स्थापित करने में सराहनीय प्रगति की है। प्रदेश में 50 हजार से भी ज्यादा विनिर्माण इकाईयां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं जिससे लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के इच्छुक संभावित निवेशकों तथा उद्यमियों को निराश नहीं होना पड़ेगा और प्रदेश सरकार उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान करेगी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव बी. के. अग्रवाल ने सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को दिए जा रहे प्रोत्साहनों की जानकारी दी।

इस अवसर पर आयोजित रात्रि भोज में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल हुए और उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट आयोजित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार को इस ग्लोबल इंवेस्टर मीट को सफल बनाने के लिए हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया।

अस्पतालों में स्वच्छता अस्पताल प्रबन्धन की प्राथमिकता होनी चाहिए:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उनसे मिलने आए आईजीएमसी के नव नियुक्त प्रिंसीपल डॉ. मुकुन्द से कहा कि अस्पतालों में साफ सफाई होना अस्पताल प्रबन्धन की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का माहौल रोगी को सकारात्मक ऊर्जा देने के साथ-साथ उसे आंतरिक बल भी प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि आईजीएमसी में पूरे हिमाचल से काफी संख्या में मरीज ईलाज के लिए आते हैं। मरीजों के साथ आए व्यक्तियों को अकसर ठहरने की समस्या आती है, जिसके लिए अस्पताल के आस-पास सराय या धर्मशाला का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी के आस-पास कोई सुविधाजनक स्थान का चयन करें, जहां सराय का निर्माण हो सके तथा साथ-साथ वर्तमान सराय में भी सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास करें।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के साथ आए तीमारदारों के लिए नहाने और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उपयुक्त स्थान बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि रोगी के साथ आए व्यक्ति भी आराम से रह सकें।

राज्यपाल ने कहा कि अस्पतालों में कई समाज सेवी संस्थाएं, सामूहिक भोजन एवं लंगर की व्यवस्था भी कर रही हैं, जिससे सदभावना और मानव सेवा की भावना बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को भी अस्पतालों के आस-पास भोजन बांटने के लिए शैड जैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे सेवा का यह कार्य व्यवस्थित हो सकेगा।

नशा एक धीमा जहर-दूर रहें इससे युवा

शिमला/शैल। सुखी जीवन का आधार नशामुक्त संसार ही है। मानव जीवन अनमोल है। सुख दुख हमारे जीवन के दो पहलू हैं, जिनके अनुभवों से हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहते हैं। जीवन में आगे बढ़ते हुए अनेक बार मनुष्य सुख और दुःख की आड़ में किसी न किसी प्रकार के नशे का सहारा लेने लगता है। कई बार युवा पीढ़ी आधुनिक दिखने की होड़ में नशे को अपना लेती है। इन सब अवस्थाओं में जीवन से भटक कर मनुष्य गलत आदतें अपना लेता है जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ता है।

युवा वर्ग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारा कुछ युवा वर्ग किशोरावस्था में ही आधुनिकता की चकाचौंध से भ्रमित होकर जिज्ञासावश नशीले पदार्थो के सेवन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें यह मालूम नहीं होता है कि वे धीरे-धीरे नशों के आदि होते जा रहे हैं और साथ-साथ लाईलाज बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं।

धुम्रपान से जहां कैंसर, सांस का रोग, दमा, खांसी इत्यादि, हृदय रोग तथा गैंगरीन जैसे लाईलाज रोग पैदा होते हैं, वहीं बीड़ी, सिगरेट से फैलने वाले धुएं से अप्रत्यक्ष रूप से गर्भवती महिलाएं व मासूम बच्चे भी भयानक रोगों की चपेट में आ जाते हैं।

नशा एक धीमा जहर है जो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर करता है। इसके लगातार सेवन से व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। नशा करने वाला

स्वयं तो मौत का ग्रास बनता ही है, लेकिन वह समाज विशेषकर अपने परिजनों के लिए भी दुख का कारण बनता है। नशा कोई भी हो, वह व्यक्ति के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास व स्मरण शक्ति को क्षीण बनाकर उसकी रचनात्मकता को दुर्बल बनाता है।

नशे के सेवन से व्यक्ति सदैव चिन्तित व उदासीन रहता है तथा हाथों में पसीना, अकेले में रहने की प्रवृति, भूख न लगना, वजन कम होना, आंखों में लाली, सूजन का होना, आवाज का लड़खड़ाना, शरीर में इन्जेक्शन लगाने के निशान तथा कपड़े मे रक्त के धब्बे, उल्टी आना, शरीर में दर्द रहना, चक्कर आना, सुस्त रहना, अत्यधिक नींद आना, थकान एवं चिडचिड़ापन, याददाशत कमजोर होने, काम में मन न लगना, दैनिक कार्यो और खेलकूद में रूचि कम होना मुख्य रूप से नशे के ही लक्षण है।

नशे का सेवन घातक है। नशे के सेवन से शारीरिक विकार जैसे मुंह, गले, लीवर, फेफड़े, दिल, गुर्दे व त्वचा में संक्रमण हो सकता है। इसके अतिरिक्त मुंह, गले, आंत, लीवर व फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। नशा परिवारिक कलह व झगड़ों को जन्म देता है। नशे के सेवन वाला व्यक्ति चोरी, डकैती, व्यभिचार, तस्करी जैसे अपराधों में संलिप्त हो जाते हैं तथा समाज ऐसे व्यक्तियों की गणना बुरे व्यक्तियों में करता है जिससे व हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं।

बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों का अहम रोल होता है। माता-पिता को चाहिए की वह बच्चों का पूरा-पूरा ध्यान रखें तथा उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तथा बच्चों व उनके साथियों की गतिविधियों पर पूरा-पूरा ध्यान रखें। बच्चों की भावनाओं व रूचियों का पूरा-पूरा ध्यान रखें। मां-बाप को चाहिए कि वह बच्चों के लिए आदर्श बनें क्योंकि वे ही यदि नशे का सेवन करेगें तो बच्चे नकल करेगें ही। यदि बच्चा नशे का शिकार है तो तुरन्त डाक्टर से परामर्श लें। समय पर उपचार से नशे से मुक्ति पाई जा सकती है।

नशे को देश से मुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और इससे होने वाली हानियों के विषय में जानकर खुद को इससे दूर रखना चाहिए। सरकार ने भी नशे पर प्रतिबंध लगाया है और यदि कोई भी व्यक्ति नशा करता या नशीले पदार्थ बेचता हुआ पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती है। लोगों को नशे की लत छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केन्द्र खोले गये हैं।

रेडक्रास के अध्यक्ष एवं उपायुक्त कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि धर्मशाला में प्रयास भवन में तथा नूरपुर में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित किये गये हैं। यहां नशा निवारण केन्द्र में हजारों की संख्या में आए नशे की बुरी लत की गिरफ्त में फसें व्यक्तियों ने नशे के सेवन से निजात पाई है। इन केन्द्रों में नशे के चुगंल से छुटकारा पाने के लिए वर्ष 2018-19 में 329 व्यक्ति जिनमें से 196 तो उपचार के लिए केन्द्र में भर्ती हुए हैं और 133 व्यक्तियों ने बाह्य रोगी के तौर पर उपचार तथा परामर्श प्राप्त किया है और सभी नशा सेवन की लत से मुक्त हो कर गए हैं।

युवा वर्ग यदि स्वस्थ, सशक्त होगा तभी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति नशीले पदार्थो के सेवन बंद कर दे। युवाओं में नशे का प्रचलन अधिक है और युवा ही देश का भविष्य है इसीलिए युवाओं को समझना चाहिए कि नशा जहर है।

गुजरात रोड शो के दौरान औद्योगिक घरानों के साथ 780 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो और हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट-2019 के दौरान उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के आवंटन में दक्षता, पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है। सरकार के इन प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश में अपनी इकाईयां स्थापित करने में उद्यमियों को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह आयोजन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सीआईआई, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से आयोजित किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने एकल खिड़की तंत्र भी विकसित किया है, जो उद्यमियों को राज्य में निवेश करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने उद्यमियों को राज्य में अपनी इकाईयां स्थापित करके हिमाचल प्रदेश की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार समस्त क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति के तहत आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है ताकि यह निवेश के लिए एक आदर्श गंतव्य बन कर उभर सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल एक शांतिप्रिय राज्य है, जहां अनुकूल औद्योगिक संबंध, अतिरिक्त ऊर्जा, कुशल श्रमशक्ति आदि उपलब्ध हैं, जो सतत् निवेश के लिए आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने गुजरात के व्यापार समुदाय से हिमाचल प्रदेश में निवेश करने पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने निवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों पर जानकारी दी और आश्वासन दिया कि राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी सरकार निवेश को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने गुजरात के निवेशकों का स्वागत करते हुए उनसे हिमाचल प्रदेश में निवेश के अवसर खोजने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव बी.के अग्रवाल ने गुजरात के उद्योग समुदाय को संबोधित करते हुए वहां के लोगों की दूरदर्शिता व उनके द्वारा अर्जित सफलता की सराहना की। उन्होंने उद्योगपतियों को एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया, जिससे इनकी निगरानी मुख्यमंत्री स्वयं ऑनलाईन कर सकें। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा व्यापार में सुगमता (ईओडीबी), भूमि बैंक और महाविद्यालय व स्कूली स्तर पर श्रम शक्ति जैसी पहल पर विस्तृत जानकारी दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन राम सुभग सिंह ने राज्य में पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अपार संभावनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहनों का विवरण दिया।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ भेंट की। एबिलॉन क्लीन एनर्जी के प्रबंध निदेशक आदित्य हांडा ने राज्य में पीपीपी मोड पर राज्य में कचरे को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।

अंबुजा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता ने राज्य में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की। ईएसएसएसीटी के सह-संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत काचरू ने थैरेपी तैयार कर वैलनेस केन्द्र खोलने में रुचि दिखाई। चंद्रेश केबल्स लिमिटेड के प्रतिनिधि अभिवंदन सी लोधा और आर.के जैन ने राज्य में केबल निर्माण इकाई स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की।

राज्य सरकार ने गुजरात रोड शो के दौरान विभिन्न औद्योगिक घरानों के साथ 780 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए, जिसमें सेंटौर एनर्जी के साथ 360 करोड़ रुपये, अल्ट्राकैब इंडिया के साथ 110 करोड़ रुपये, गुजरात अंबूजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ 100 करोड़ रुपये, ईएसएसएसीटी प्रोजेक्ट (क्रिएटिव च्वाइस ग्रुप) के साथ 100 करोड़ रुपये जेजेपीवी सोलर के साथ 40 करोड़ रुपये मै. चंद्रेश केबलस के साथ 40 करोड़ रुपये, ईशान नेट सोल के साथ 20 करोड़ रुपये व ब्लू रे एविऐशन के साथ राज्य में उनकी इकाइयां स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

हिमाचल में सैन्य हवाई अड्डे की मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की तथा उनसे हिमाचल में सैन्य हवाई अड्डे की स्थापना की मांग उठाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों व सैन्य अभियान के लिए चंडीगढ़

के अतिरिक्त इस क्षेत्र में कोई भी रक्षा हवाई अड्डा उपलब्ध नही है, जिसके अभाव में किसी विपरीत स्थिति से निपटना कठिन है। उन्होंने कहा कि इसलिए सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जिला मंडी में एक रक्षा हवाई अड्डे की स्थापना करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस हवाई अड्डे को नागरिक उद्देश्य के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जिससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की आर्थिकी भी समृद्ध होगी।

मुख्मयंत्री ने रक्षा मंत्री को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने मंडी जिला में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का निर्माण प्रस्तावित किया है, जिसके लिए नागचला में 3479 बीघा भूमि का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नई दिल्ली की टीम द्वारा निरीक्षण व सर्वेक्षण कर लिया है। सर्वेक्षण के उपरान्त इस स्थान को हवाई पट्टी की स्थापना के लिए उपयुक्त पाया है।

उन्होंने कहा कि जिला मंडी प्रदेश के सभी स्थलों के केंद्र में पड़ता है और साथ लगते सीमा क्षेत्रों की ओर जाने के लिए भी सड़क मार्ग पर स्थित है। उन्होंने रक्षा मंत्री से इस प्रस्तावित हवाई अड्डे को रक्षा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि उनकी इस मांग पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा, कांगड़ा के सांसद किशन कपूर और शिमला के सांसद सुरेश कश्यप भी मुख्यमंत्री के साथ थे।

1892 करोड़ से निखरेगा हिमाचल का पर्यटन

शिमला/शैल। वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा हिमाचल में पर्यटन विकास पर 1892 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रदेश की नई राहें नई मजिलें योजना के तहत ये धनराशि मंजूर की है। योजना के तहत प्रदेश के अनछुए पर्यटन गणतव्यों को विकसित किया जाएगा। इसके तहत जंजैहली समेत चांशल और

बीड़-बिलिंग क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। गोविंद सिंह ठाकुर चार दिवसीय जंजैहली पर्यटन महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहा थे।

इस अवसर जनसभा को संबोधित करते हुए गोबिंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को प्राकृतिक सम्पदा से नवाजा है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। जंजैहली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहां पर्यटन को विकसित करने के लिए जंजैहली पर्यटन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, ताकि जंजैहली को पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर लाया जा सके।

उन्होंने कहा मुख्यमंत्री देश-विदेश से हिमाचल में निवेश लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। नवम्बर माह में धर्मशाला में ग्लोबल इनवेस्टर आयोजित की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रदेश में एक लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावना हैं।

वन विभाग सराज विधानसभा क्षेत्र में विकास गतिविधियों पर 20 करोड़ रूपये खर्च रहा है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सराज क्षेत्र के लिए 15 नए बस रूट चलाए गए हैं । कांगणी-शिकारी, शिकारी-कटारू के लिए हैली टैक्सी पैड पर 50 करोड़ रूपये खर्च किए जा रहे हैं। सराज क्षेत्र में 27 करोड़ रूपये की लागत से पर्यटक केंद्र का निर्माण किया जा रहा है।

उन्होंने कहा वन सम्पदा हमारी धरोहर है तथा इस बचाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने लोगों से बरसात में दौरान अधिक से अधिक पौधरोपण करने का आह्वान किया।

वन मंत्री ने महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर 19 महिला मंडलों द्वारा निकाली गयी झांकी के लिए दस-दस हजार रूपये तथा महोत्सव आयोजन समिति को 25 हजार रूपये देने की घोषणा की। उन्होंने ढीमकटारू पंचायत के चार युवक मंडलों को बालीबाल व किक्रेट किट देने, जंजैहली स्कूल में बैडमिंटन कोर्ट तथा इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की ।

एसडीएम थुनाग सुरेन्द्र मोहन शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए उत्सव की जानकारी दी। जंजैहली पर्यटन महोत्सव के माध्यम से अनेक गतिविधियां चलाई जा रही है । जिसमें मैलोडी ऑफ सराज का पहला राउंड आयोजित किया गया।

इस मौके पर वन मंत्री की धर्म पत्नी रजनी ठाकुर, विभिन्न बोर्डो के निदेशक मंडल के सदस्य शेर सिंह, भीषम, पीताम्बर, कमल राणा, जिला परिषद सदस्य कमल किशोर, प्रधान ढीमकटारू पंचायत हुक्मा देवी, अरण्यपाल उपासना पटियाल, वन मंडलाधिकारी टीआर धीमान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

वर्ष 2022 के प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाएं कार्यकर्ता:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से 2022 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी में जुटने का आहवान किया है। मुख्यमंत्री ने मंडी में भाजपा सदस्यता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए

पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनावी दिनों में ही तैयारी करने वाली पार्टी नही है, समर्पित कार्यकर्ता व नेता लगातार लोगों के बीच रहते हैं जिसके फलस्वरूप पार्टी को सफलता मिली है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनावों में मिली बड़ी सफलता का आधार सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय और लंबी तैयारी है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए कमर कस ली थी। प्रधानमंत्री ने सरकार के स्तर पर और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने संगठन के सामने पिछली जीत से बड़ी जीत का लक्ष्य रख कर काम किया और परिणाम सबके सामने है।

उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2017 में हमारी सरकार बनते ही लोकसभा चुनावों में लक्ष्य सामने रख कर चारों सीटें बड़े मार्जिन से जीतने की ठानी थी। आप सभी के सहयोग से लोकसभा चुनाव में जीत का नया इतिहास बना है। न केवल पार्टी का वोट शेयर बढ़ा बल्कि सभी 68 विधानसभा के क्षेत्रों में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आवश्यक है कि जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों में पार्टी को वोट दिया, उन्हें पार्टी के विचार से जोड़ा जाए। हमें वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अभी से कमर कसनी है। केंद्रीय नेतृत्व को हिमाचल से बहुत अपेक्षाएं हैं, उन्हें पूरा करने और प्रदेश में बार-बार भाजपा सरकार लाने के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान में अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी की विचारधारा पहुंचाएं, नए सदस्य बनाएं। नए कार्यकर्ता बनाने में डिजिटल प्लेटफार्म सहित अभी साधनों का उपयोग करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

shailsamachar.co.in

क्या सरकार का कर्जा और घाटा राजस्व आय से बढ़ना अच्छा आर्थिक प्रबन्धन है

शिमला/शैल। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की वित्त मन्त्री सीतारमण ने वर्ष 2019 – 20 के अपने दो घन्टे के बजट भाषण में जहां सरकार की विभिन्न आर्थिक योजनाओं का जिक्र देश के सामने रखा वहीं पर उन्होने आंकड़ो का कोई खुलासा नही किया। ऐसा शायद पहली बार हुआ है अन्यथा बजट में सरकार की आय – व्यय की पूरी विस्तृत जानकारी भाषण में रहती है। जब भी सरकार को बजट सामने आता है उसका तत्काल प्रभाव शेयर बाज़ार पर पड़ता है। शेयर बाज़ार पर इस बार भी असर पड़ा और करीब 6 लाख करोड़ निवेशकों का डूब गया। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे बजट दस्तावेजों को देखने – समझने की जिज्ञासा होना स्वभाविक था।

इन दस्तावेजों के मुताबिक सरकार वर्ष 2019 – 20 में कुल 27,86,349 करोड़ खर्च करेगी। यह खर्च मोटे तौर पर कहां – कहां खर्च होगा उसका विवरण इस प्रकार है।

मद	
पेंशन	1,74,300
रक्षा	3,05,296
प्रमुख सब्सिडी	3,01,694
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	1,51,518
वाणिज्य और उद्योग	27,043
पूर्वोत्तर का विकास	3,000
शिक्षा	94,854
ऊर्जा	44,638
विदेश मामले	17,885
वित्त	20,121
स्वास्थ्य	64,999
गृह	1,03,927
ब्याज	6,60,471
आईटी और दूरसंचार	21,783
योजना एवं सांख्यिकी	5,814
ग्रामीण विकास	1,40,762
वैज्ञानिक विभाग	27,431
सामाजिक कल्याण	50,850
कर प्रशासन	1,17,285
राज्यों को अंतरण	1,55,447
परिवहन	1,57,437
संघ राज्य क्षेत्र	15,098
शहरी विकास	48,032
अन्य	76,665
कुल जोड़	27,86,349

लेकिन इस खर्च के लिये जो आय के साधन रहेंगे उनमें सबसे बड़ा साधन है सरकार की राजस्व आय जिसमें कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों शामिल रहते हैं। सरकार की यह राजस्व आय वर्ष 2019 – 20 के लिये 19,62,761 करोड़ रहेगी और 27,86,349 करोड़ का कुल खर्च पूरा करने के लिये विभिन्न ऋणों के माध्यम से इस बार 8,23,588 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां जुटाई जायेंगी। इन पूंजीगत प्राप्तियों के साथ इस वर्ष का खर्चा तो पूरा हो जाता है लेकिन अब तक जो राजकोषीय और राजस्व का घाटा खड़ा है वह चिन्ता और चिन्तन का विषय बन जाता है। बजट दस्तावेजों के मुताबिक यह घाटा और कर्जा मिलकर सरकार की राजस्व आय से करीब तीन लाख करोड़ से भी अधिक हो जाता है। राजस्व प्राप्तियों, पूंजीगत प्राप्तियों और घाटे का विवरण इस प्रकार है।

कर्जे और घाटे की आर्थिक व्यवस्था उस समय चिन्ता का विषय बन जाती है जब सरकार को अपने विभिन्न अदारों में विनिवेश करके राजस्व जुटाने की स्थिति आ जाये। बजट से पहले यह चर्चा थी कि सरकार 90,000 करोड़ विनिवेश से जुटायेगी। लेकिन बजट दस्तावेजों के मुताबिक सरकार अब 1.5 लाख करोड़ विनिवेश से हासिल करेगी। इस विनिवेश से

(in ₹ crore)

	2017-18 (Actuals)	2018-19 (Budget Estimates)	2018-19 (Revised Estimates)	2019-20 (Budget Estimates)
Revenue Receipts	14,35,233	17,25,738	17,29,682	19,62,761
Capital Receipts	7,06,740	7,16,475	7,27,553	8,23,588
Total Receipts	21,41,973	24,42,213	24,57,235	27,86,349
Total Expenditure	21,41,973	24,42,213	24,57,235	27,86,349
Revenue Deficit	4,43,600	4,16,034	4,10,930	4,85,019
Effective Revenue Deficit	2,52,566	2,20,689	2,10,630	2,77,686
Fiscal Deficit	5,91,062	6,24,276	6,34,398	7,03,760
Primary Deficit	62,110	48,481	46,828	43,289

एक समय तो सरकार को आय हो जाती है लेकिन भविष्य के लिये वह संसाधन सरकार के हाथ से निकल जाता है। परन्तु इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या सारा घाटा विनिवेश और आम आदमी पर करों का बोझ लाद कर पूरा किया जा सकता है? फिर पूंजीगत प्राप्तियों की तो परिभाषा ही यह है कि इसका निवेश तो विकासात्मक कार्यो और राजस्व के नये साधन जुटाने के लिये हो। लेकिन बजट दस्तावेजों के अवलोकन से इस धारणा पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

केन्द्र कर्ज और संपति बेचकर जुटायेगा 8,23,588.42 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां

केन्द्र सरकार का वर्ष 2019 – 20 के बजट आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष सरकार का कर्जा और घाटा उसकी राजस्व आय से काफी अधिक बढ़ने जा रहा है। सरकार 27,86,349 करोड़ का खर्च पूरा करने के लिये 8,23,588.42 लाख करोड़ की पूंजीगत प्रप्तियां कर्ज लेकर जुटा रही हैं यह कर्ज कहां – कहां से लिया जायेगा उसका विवरण इस प्रकार रहेगा।

Receipt Budget, 2019-2020 13

Capital Receipts

(In ₹ crores)

	Major Head	Actual 2017-18	Budget 2018-19	Revised 2018-19	Budget 2019-20
Non Debt Receipts					
1. Recoveries of Loans & Advances					
1.01. State Governments					
1.01.01. Gross Receipts	7601	13057.30	9166.74	8902.93	11614.81
1.01.02. Recoveries	7601	...	-100.00	-100.00	-100.00
Net-State Governments		*13057.30*	*9066.74*	*8802.93*	*11514.81*
1.02. Union Territories (With Legislature)	7602	66.81	432.69	442.69	442.69
1.03. Foreign Governments	7605	353.73	325.29	348.34	145.17
1.04. Other Loans & Advances (Public Sector Enterprises, Statutory Bodies etc.)					
1.04.01. Gross Receipts	9001	57161.32	53649.36	55061.20	54000.06
1.04.02. Recoveries	9001	-55005.88	-51275.00	-51500.00	-51275.01
Net-Other Loans & Advances (Public Sector Enterprises, Statutory Bodies etc.)		*2155.44*	*2374.36*	*3561.20*	*2725.05*
Net-Recoveries of Loans & Advances		*15633.28*	*12199.08*	*13155.16*	*14827.72*
2. Miscellaneous Capital Receipts					
2.01. Disinvestment Receipts	4000	100045.05	80000.00	80000.00	105000.00
2.02. Issue of Bonus Shares	4000	3.40	...	252.18	...
2.03. Receipts netted with Bonus Shares	4000	-3.40	...	-252.18	...
Net-Miscellaneous Capital Receipts		*100045.05*	*80000.00*	*80000.00*	*105000.00*
Total-Non Debt Receipts		**115678.33**	**92199.08**	**93155.16**	**119827.72**
Debt Receipts					
3. Borrowings					
3.01. Market Loans					
3.01.01. Gross Borrowings	6001	588000.00	605539.36	571000.00	710000.00
3.01.02. Repayments	6001	-137271.69	-143477.87	-148263.08	-236877.99
Net-Market Loans		*450728.31*	*462061.49*	*422736.92*	*473122.01*
3.02. Issuance of Special Securities to Public Sector Banks					
3.02.01. Issue of Securities	6001	80000.00	65000.00	106000.00	70000.00
3.02.02. Repayments	6001	...	...	...	...
3.02.03. Less Receipts netted	6001	-80000.00	-65000.00	-106000.00	-70000.00
Net-Issuance of Special Securities to Public Sector Banks		...	...	...	...
3.03. Issuance of Special Securities to EXIM Bank					
3.03.01. Issue of Securities	6001	...	...	4500.00	550.00
3.03.02. Repayments	6001	...	...	...	...
3.03.03. Less Receipts netted	6001	...	...	-4500.00	-550.00
Net-Issuance of Special Securities to EXIM Bank		...	...	...	...
3.04. Switching of Securities					
3.04.01. Gross Borrowings	6001	59158.98	28059.00	28059.00	50000.00
3.04.02. Repayments	6001	-58075.00	-28059.00	-28059.00	-50000.00
Net-Switching of Securities		*1083.98*	...	...	...
3.05. Buyback					
3.05.01. Gross Borrowings	6001	...	...	...	...
3.05.02. Repayments	6001	-41555.07	-71941.00	...	-50000.00
Net-Buyback		*-41555.07*	*-71941.00*	...	*-50000.00*
3.06. Short Term Borrowings					
3.06.01. 14 Days Treasury Bills					
3.06.01.01. Gross Borrowings	6001	3790637.92	4027581.00	3771818.30	3960409.22
3.06.01.02. Repayments	6001	-3796169.17	-4027581.00	-3771818.30	-3960409.22
Net		*-5531.25*	...	...	...
3.06.02. 91 Days Treasury Bills					
3.06.02.01. Gross Borrowings	6001	774059.95	857721.45	663316.47	545344.72
3.06.02.02. Repayment	6001	-742174.08	-857721.45	-706707.70	-524343.22
Net		*31885.87*	...	*-43391.23*	*21001.50*
3.06.03. 182 Days Treasury Bills					
3.06.03.01. Gross Borrowings	6001	185416.61	169705.32	258769.34	312168.86
3.06.03.02. Repayments	6001	-183981.05	-161705.32	-225089.11	-310119.02
Net		*1435.56*	*8000.00*	*33680.23*	*2049.84*
3.06.04. 364 Days Treasury Bills					
3.06.04.01. Gross Borrowings	6001	159685.00	158993.00	194396.00	192344.66
3.06.04.02. Repayments	6001	-142525.75	-149993.00	-159685.00	-190396.00
Net		*17159.25*	*9000.00*	*34711.00*	*1948.66*
3.06.05. Cash Management Bills					
3.06.05.01. Gross Borrowings	6001	150000.00	100000.00	200000.00	100000.00
3.06.05.02. Repayments	6001	-150000.00	-100000.00	-200000.00	-100000.00
Net		...	...	...	...
3.06.06. Ways & Means Advances					
3.06.06.01. Gross Borrowings	6001	480042.00	500000.00	900000.00	500000.00
3.06.06.02. Repayments	6001	-480042.00	-500000.00	-900000.00	-500000.00
Net		...	...	...	...
Net-Short Term Borrowings		*44949.43*	*17000.00*	*25000.00*	*25000.00*
Net-Borrowings		*455206.65*	*407120.49*	*447736.92*	*448122.01*
4. Securities against Small Savings					
4.01. Receipts	6001	108661.00	88533.00	138533.00	152268.32
4.02. Repayments	6001	-6033.05	-13533.00	-13533.00	-22268.32
Net-Securities against Small Savings		*102627.95*	*75000.00*	*125000.00*	*130000.00*
5. State Provident Funds					
5.01. Receipts	8009	61483.20	65000.00	72000.00	77000.00
5.02. Disbursements	8009	-45684.53	-48000.00	-55000.00	-59000.00
Net-State Provident Funds		*15798.67*	*17000.00*	*17000.00*	*18000.00*
6. Other Receipts (Internal Debts and Public Account)					
6.01. Relief Bonds					
6.01.01. Receipts	6001	...	...	...	...
6.01.02. Disbursements	6001	-2.50	-54.88	-68.01	-14.37
Net-Relief Bonds		*-2.50*	*-54.88*	*-68.01*	*-14.37*
6.02. Saving Bonds					
6.02.01. Receipts	6001	24830.87	20177.17	21220.11	27273.95
6.02.02. Disbursements	6001	-622.35	-811.09	-1854.03	-1823.18
Net-Saving Bonds		*24208.52*	*19366.08*	*19366.08*	*25450.77*
6.03. Other (Gold Bonds, Gold Monetisation etc.)					
6.03.01. Receipts	6001	1894.82	5000.00	5000.00	5000.00
6.03.02. Disbursements	6001	...	...	...	...
Net-Other (Gold Bonds, Gold Monetisation etc.)		*1894.82*	*5000.00*	*5000.00*	*5000.00*
6.04. Other Receipts (Public Account Other than State Provident Funds)					
6.04.01. Receipts	9002	1366775.36	1377490.60	1421807.28	1564804.08
6.04.02. Disbursements	9002	-1382555.73	-1316482.49	-1432602.39	-1534136.10
6.04.03. Less Receipts	9002	...	...	...	...
Net-Other Receipts (Public Account Other than State Provident Funds)		*-15780.37*	*61008.11*	*-10795.11*	*30667.98*
6.05. International Financial Institutions					
6.05.01. International Monetary Fund					
6.05.01.01. Receipts	6001	2554.50	0.01	9278.35	100.01
6.05.01.02. Repayments	6001	-7140.04	-100.00	-4587.80	-1000.00
6.05.01.03. Less Receipts netted	6001	-543.18	-511.62	-9792.90	-583.78
Net		*-5128.72*	*-611.61*	*-5102.35*	*-1483.77*
6.05.02. International Development Association					
6.05.02.01. Receipts	6001	408.33	408.34	408.34	408.34
6.05.02.02. Repayments	6001	-156.87	-357.36	-389.88	-370.29
Net		*251.46*	*50.98*	*18.46*	*38.05*
6.05.03. Asian Development Bank and Fund					
6.05.03.01. Receipts	6001	64.50	66.03	68.97	72.01
6.05.03.02. Repayments	6001	-136.92	-152.82	-145.24	-172.92
Net		*-72.42*	*-86.79*	*-76.27*	*-100.91*
6.05.04. African Development Fund and Bank					
6.05.04.01. Receipts	6001	70.35	37.24	37.24	3.42
6.05.04.02. Repayments	6001	-33.83	-30.58	-27.34	-29.56
Net		*36.52*	*6.66*	*9.90*	*-26.14*
Net-International Financial Institutions		*-4913.16*	*-640.76*	*-5150.26*	*-1572.77*
Net-Other Receipts (Internal Debts and Public Account)		*5407.31*	*84678.55*	*8352.70*	*59531.61*
7. External Debt					
7.01. Multilateral					
7.01.01. International Bank for Reconstruction and Development					
7.01.01.01. Receipts	6002	6851.92	6601.85	7257.00	7831.00
7.01.01.02. Repayments	6002	-5444.53	-5887.77	-6474.77	-7351.49
Net		*1407.39*	*714.08*	*782.23*	*479.51*
7.01.02. International Development Association					
7.01.02.01. Receipts	6002	8687.32	7406.69	6932.00	6756.00
7.01.02.02. Repayments	6002	-11110.36	-12083.79	-13077.69	-14479.46
Net		*-2423.04*	*-4677.10*	*-6145.69*	*-7723.46*
7.01.03. International Fund for Agricultural Development					
7.01.03.01. Receipts	6002	276.66	471.90	332.00	373.00
7.01.03.02. Repayments	6002	-91.48	-95.83	-104.10	-134.60
Net		*185.18*	*376.07*	*227.90*	*238.40*
7.01.04. Asian Development Bank					
7.01.04.01. Receipts	6002	10320.12	9199.81	10055.00	10093.00
7.01.04.02. Repayments	6002	-3412.75	-4316.67	-4119.27	-4853.25
Net		*6907.37*	*4883.14*	*5935.73*	*5239.75*
7.01.05. Eastern European Community (SAC)					
7.01.05.01. Receipts	6002	...	...	...	...
7.01.05.02. Repayments	6002	-8.21	-8.63	-9.21	-9.49
Net		*-8.21*	*-8.63*	*-9.21*	*-9.49*
7.01.06. Organisation of the Petroleum Exporting Countries					
7.01.06.01. Receipts	6002	-0.01	...	...	...
7.01.06.02. Repayments	6002	-11.67	-12.04	-15.86	-15.98
Net		*-11.68*	*-12.04*	*-15.86*	*-15.98*
7.01.07. New Development Bank					
7.01.07.01. Receipts	6002	137.21	200.00	1083.00	1089.00
7.01.07.02. Repayments	6002	...	...	...	...
Net		*137.21*	*200.00*	*1083.00*	*1089.00*
7.01.08. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)					
7.01.08.01. Receipts	6002	374.13	50.00	1108.00	653.00
7.01.08.02. Repayments	6002	...	...	...	...
Total-Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)		*374.13*	*50.00*	*1108.00*	*653.00*
Net-Multilateral		*6568.35*	*1525.52*	*2966.10*	*-49.27*
7.02. Bilateral					
7.02.01. Germany					
7.02.01.01. Receipts	6002	1858.46	2317.01	1289.00	1022.00
7.02.01.02. Repayments	6002	-928.64	-1154.79	-1202.80	-1419.06
Net		*929.82*	*1162.22*	*86.20*	*-397.06*
7.02.02. France					
7.02.02.01. Receipts	6002	1045.15	751.75	731.00	1519.00
7.02.02.02. Repayments	6002	-173.75	-213.71	-232.46	-308.69
Net		*871.40*	*538.04*	*498.54*	*1210.31*
7.02.04. Japan					
7.02.04.01. Receipts	6002	15818.91	10776.38	7954.00	10156.00
7.02.04.02. Repayments	6002	-4612.58	-4766.47	-5153.59	-5800.89
Net		*11206.33*	*6009.91*	*2800.41*	*4355.11*
7.02.05. Switzerland					
7.02.05.01. Receipts	6002	...	...	...	...
7.02.05.02. Repayments	6002	-0.33	-0.16	-0.16	...
Net		*-0.33*	*-0.16*	*-0.16*	...
7.02.06. USA					
7.02.06.01. Receipts	6002	83.91	...	...	...
7.02.06.02. Repayments	6002	-162.86	-167.21	-178.96	-176.40
Net		*-78.95*	*-167.21*	*-178.96*	*-176.40*
7.02.07. Russian Federation					
7.02.07.01. Receipts	6002	2301.55	2807.00	2624.00	3915.00
7.02.07.02. Repayments	6002	-728.11	-747.93	-771.13	-813.69
Net		*1573.44*	*2059.07*	*1852.87*	*3101.31*
7.02.08. European Investment Bank (EIB)					
7.02.08.01. Receipts	6002	761.41	300.00	844.00	1266.00
7.02.08.02. Repayments	6002	...	...	...	...
Net		*761.41*	*300.00*	*844.00*	*1266.00*
Net-Bilateral		*15263.12*	*9901.87*	*5902.90*	*9359.27*
7.03. Expenditure netted against externally assistance for States Projects	6002	-13900.73	-14016.00	-13762.12	-12262.05
Net-External Debt		*7930.74*	*-2588.61*	*-4893.12*	*-2952.05*
8. Draw Down of Cash Balance					
8.01. Receipts	9003	5498.61	44877.61	1407.86	-39793.06
8.02. Disbursements	9003	-1407.86	-1811.61	39793.06	90852.19
Net-Draw Down of Cash Balance		*4090.75*	*43066.00*	*41200.92*	*51059.13*
9. Market Stabilisation Scheme					
9.01. Receipts	6001	100000.00	...	...	...
9.02. Repayments	6001	-100000.00	...	...	...
Net-Market Stabilisation Scheme		...	...	...	...
Total-Debt Receipts		**591062.07**	**624276.43**	**634397.42**	**703760.70**
Grand Total		***706740.40***	***716475.51***	***727552.58***	***823588.42***